भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 496

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार

496. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों का ब्यौरा क्या है और 2025 तक दादरा और नगर हवेली सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है;

(ख) कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बीपीएल परिवार के सदस्यों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीपीएल परिवारों की पहचान के मानदंडों को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बीपीएल परिवारों के लिए लक्षित लाभों और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को समेकित और सुव्यवस्थित करने के लिए एकल डिजिटल पोर्टल विकसित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हाँ, तो दादरा और नगर हवेली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) वर्ष 2021 में, सरकार ने गरीबी के आकलन के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नामक एक व्यापक सूचकांक विकसित किया, जो 12 संकेतकों को

शामिल करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में व्याप्त अतिव्यापी अभावों को दर्शाता है। इस सूचकांक का दूसरा संस्करण 2023 में जारी किया गया। नवीनतम राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो इस बात को दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.55 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित चर्चा पत्र '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी के 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% होने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

दादरा और नगर हवेली एवं महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन प्रमुख आयामों को शामिल करने वाले एमपीआई डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf पर देखा जा सकता है।

गरीबी में यह उल्लेखनीय कमी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित इन पहलों का उद्देश्य कमज़ोर समूहों की सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना है। इन योजनाओं से संबंधित आँकड़े संबंधित मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, जहाँ प्रत्येक मंत्रालय विशिष्ट कार्यक्रमों की देखरेख करता है और समर्पित पोर्टलों के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

(ख) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और अप-स्किलिंग प्रशिक्षण प्रदान करती है।

*****